

करण क. निगरानी / 2014

प्रस्तुति दिनांक : ०७/०४/२०१४

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर

फॉर्म - १३५२ - पृ० २ - १२

ओंकारसिंह पिता बोदरासेंह

निवासी - ग्राम खाकरोड तहसील सांवेर

जिला इन्दौर

-- प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमती लक्ष्मीबाई पति त्रिलोकचंद्र चौकसे

निवासी - ४९/२, गेघदूत नगर, इन्दौर

-- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.सं. १९५९

माननीय न्यायालय में यह निगरानी आवेदन माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा उनके न्यायालयीन प्र.क. 252 अप्रैल / 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2014 के विरुद्ध निम्न आधारों पर नियत समयावधि में प्रस्तुत है -

मुख्य नोट R-362-पोबौआर/ 2014.

जिला इंडी

मुख्य नोट

मुख्य नोट

मुख्य नोट

आदि इंडी

17-7-2014

आवेदक के विद्वान अभिभावक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तँड़ पर विचार किया गया। अपर आयुक्त जे आदेश दिनांक 11-2-2014 की सत्य प्रतिलिपि का अनुवाद किया गया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा पंजीकृत विक्य पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है। पंजीकृत विक्य पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है। तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा कब्जे के बाबत पर नामांतरण का लक्ष्य न आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि कब्जे के आधार पर नामांतरण के कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है। और न ही मत्र व्यवहार याद प्रतिलिपि होने से नामांतरण की कार्यवाही रोकी जा सकती है। उद्य तक के व्यवहार न्यायालय द्वारा रक्षण आदेश नहीं जारी किया गया है। व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश राजस्व न्यायालयों पर बधनकारी है और व्यवहार न्यायालय द्वारा दाखित निर्णय के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा पुनः कार्यवाही को जा सकती है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुवेभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त तो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फलस्वरूप यह निराशी प्रधान दृष्टया आधारहीन होने से अग्रहय की जाती है।

(रवदीप सिंह)

अध्यक्ष